

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी वाडमेर  
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

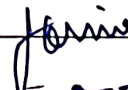
दिनांक 22.06.2023

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री रामस्वरूप भाटी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि प्रार्थीगण के पूर्वज भोलाराम पुत्र कानाराम उर्फ रामाराम की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी भूमि मौजा महाबार में खसरा संख्या 51 रकवा 105.4 बीघा दर्ज थी। विप्रार्थीगण ने गलत तथ्यों को प्रकट करते हुए स्वयं को जटिया जाति का बताकर भोला से दिनांक 16.06.1961 को एक बेचान नामा उक्त खसरान की भूमि बाबत निष्पादित करवा दिया। जबकि उक्त विप्रार्थीगण जटिया जाति के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वर्ण जाति के तहत कुम्हार जाति के व्यक्ति थे, जिनका बेचान धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत शून्य है इस आशय का वाद मय दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते रेस्पोंडेंटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो रेस्पोंडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। अपीलांट को रेस्पोंडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
वाडमेर

अधिवक्ता अपीलांटस की पत्रावली पर वहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना-पत्र में पारित आदेश के विरुद्ध पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलांटगण के कब्जा काश्त में रेस्पोंडेंटस द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2022 को अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोंडेंटस को पाबंद किया जाता है कि वे मौजा महाबार तहसील बाड़मेर के पुराना खसरा संख्या 51 रकबा 105.04 बीघा (नवीन खसरा संख्या 2486/51 रकबा 84.04 बीघा व खसरा संख्या 2485/51 रकबा 21 बीघा) भूमि का बेचान नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 22.06.2023 को सुनाया गया।

*J. Saniv*  
(पब्लिक प्रोसेक्यूटोर)  
राजस्थान असाईल प्राधिकारी  
बाड़मेर